प्रेस रिलीज़

पंद्रहवीं असर (एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट) रिपोर्ट 2020-प्रथम चक्र आज जारी

देश में शिक्षा गुणवत्ता का वार्षिक आकलन करने वाली चर्चित असर 2020 रिपोर्ट (प्रथम चक्र) दुनिया भर के प्रतिभागियों के बीच बुधवार को ऑनलाइन जारी की गई। यह असर की 15वीं वार्षिक रिपोर्ट है।

वर्ष 2005 से 2014 असर के तहत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों के स्तर और 5-16 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों की पढ़ने व बुनियादी गणित करने की क्षमता की प्रतिवर्ष जांच की जाती है। लगातार दस वर्षों तक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद 2016 से असर हर दूसरे वर्ष (2016, 2018) इस तरह के 'बुनियादी' सर्वेक्षण को सामने ला रहा है। इस सर्वेक्षण में बच्चों की शिक्षा व सीखने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर नज़र रखी जाती है। वर्ष 2017 में असर ने 14-18 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का 'बुनियादी से आगे' की क्षमताओं, अनुभवों औरआकांक्षाओं को परखने का प्रयास किया। वर्ष 2019 में असर की 'वार्षिक रिपोर्ट' में 4-8 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों की शुरुआती मुख्य भाषाई वगणितीय क्षमताओं तथा संज्ञानात्मक व सामाजिक-भावनात्मक संकेतकों का जायजा लिया गया।

वर्ष 2020 में कोविड-19 15 वर्षों से जारी इस यात्रा में बाधा बनकर खड़ा हो गया। लेकिन देशभर में बच्चों की शिक्षा व सीखने के अवसरों पर इस महामारी के प्रभावों को व्यवस्थित तरीके से समझने की ज़रूरत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। हालांकि बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए भारी मात्रा में डिजिटल पाठ्यसामग्री तैयार व वितरित की जा रही थी, लेकिन इस बात के सीमित प्रमाण मिल रहे थे कि कितने बच्चों तक यह सामग्री पहुंच पा रही है। क्या वे इसकी मदद से पढ़ पा रहे हैं? और उनकी भागीदारी व समझ में इसका कोई असर पड़ भी रहा है?

असर 2020 पहला फोन आधारित असर सर्वेक्षण है। देश में स्कूल बंदी के छः महीने बाद सितंबर 2020 में सम्पन्न यह सर्वेक्षण ग्रामीण भारत के बच्चों के लिए दूर शिक्षा की प्रक्रियाओं, पाठ्य सामग्रियों, गतिविधियों की व्यवस्थाओं व पहुंच की पड़ताल करता है। साथ ही उन तौर-तरीकों का भी जायजा लेता है जिसमें बच्चे और उनके परिवार अपने घर से दूर शिक्षा के इन विकल्पों तक पहुंच पा रहे हैं।

असर 2020 का दायरा 26 राज्यों व 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित था। इसके माध्यम से 52,227 घरों व 5-16 वर्ष की आयु के 59,251 बच्चों के अलावा 8,963 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों अथवा प्रधानाध्यापकों तक पहुंच बनी।

असर 2020 का दायरा गुजरात में 3,303 घरों व 5-16 वर्ष की आयु के 1,892 बच्चोंतक पहुंच बनी।

असर 2020 के निष्कर्ष:

विद्यालयों में नामांकन के पैटर्न

विद्यालयों में नामांकन में बदलावों का ठीक-ठीक आकलन तभी हो पाएगा जब विद्यालय फिर से खुलेंगे और बच्चे कक्षाओं में लौट पाने की स्थिति में होंगे। वर्ष 2018 की तुलना में असर 2020 के हमारे अंतरिम आकलन बताते हैं कि:

- **अखिल भारतीय स्तर पर सरकारी विद्यालयों की ओर हल्का सा रुझान दिखता है।** असर 2018 के साथ असर 2020 (सितंबर 2020) के आंकड़ों की तुलना बताती है कि सभी कक्षाओं में और लड़के व लड़कियों दोनों में, निजी से सरकारी विद्यालयों की ओर नामांकन का रुझान हल्का सा बढ़ा है। 2020 में सरकारी विद्यालयों में लड़कों के नामांकन का प्रतिशत 66.4% पर आ गया जबकि 2018 में य 62.8% था। इसी तरह इसी अवधि में सरकारी विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत 70% से बढ़कर 73% हो गया।

गुजरातमें 2020 में सरकारी विद्यालयों में लड़कों के नामांकन का प्रतिशत 82.7% पर आ गया जबकि 2018 में य 83.3% था। इसी तरह इसी अवधि में सरकारी विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत 87.2 से घटकर86.2 हो गया।

- कई छोटे बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश अब भी बाकी है। असर 2020 बताता है कि जहां सत्र 2020-21 में विद्यालय में प्रवेश नहीं लेने वाले बच्चों का हिस्सा वर्ष 2018 की तुलना में ज्यादा है, ज्यादातर आयुवर्गों में यह अंतर बहुत कम है। विद्यालय में नामांकित नहीं होने वाले बच्चों में अधिकतर कम उम्र (6 और 7 वर्ष) के दिखाई देते हैं। ऐसा संभवतः उनके विद्यालयमें प्रवेश नहीं हो पाने के कारण हुआ होगा। यह अनुपात खास तौर पर कर्नाटक (यहां 6 और 7 के 11.3% बच्चों का 2020 में नामांकन नहीं हुआ है), तेलंगाना (14%) और राजस्थान (14.9%)।

गुजरात में 6 से 10 वर्ष 2018 में 0.7% बच्चों कानामांकन नहीं हुआ था जो 2020 में 1.2% बच्चों कानामांकन नहीं हुआ है

पारिवारिक संसाधन

जबकि विद्यालय बंद हैं, बच्चे सीखने के लिए मुख्यतः घर में उपलब्ध संसाधनों व मदद पर निर्भर हैं। इन संसाधनों में परिजन भी शामिल हैं जो पढ़ाई में उनकी मदद करते हैं (जैसे शिक्षित माता-पिता)। इसके अलावा टेक्नोलॉजी (टीवी, रेडियो या स्मार्टफोन) या पाठ्यसामग्री (जैसे मौजूद कक्षा की पाठ्यपुस्तकें)।

- विद्यालयों में आने वाले बच्चों में बहुत थोड़े ही पहली पीढ़ी के विद्यालय यात्री हैं। औसतन चार में तीन से ज्यादा बच्चों के माता-पिता में कम से कम एक ने प्राथमिक (कक्षा 5) स्तर या उससे ज्यादा शिक्षा पाई है। एक चौथाई से ज्यादा बच्चों के माता-पिता दसवीं या उससे ज्यादा पढ़े हैं।
- नामांकित बच्चों में से 60% से ज्यादा ऐसे परिवारों में रहते हैं, जिसमें कम से कम एक स्मार्टफोन है। यह प्रतिशत पिछले दो वर्षों में बहुत बढ़ा है, जो नामांकित बच्चों के बीच 36.5% से बढ़कर 61.8% हो गया है। प्रतिशत में यह बढ़ोतरी सरकारी व निजी दोनों तरह के विद्यालयों में नामांकित बच्चों के घरों में एक जैसी है। राज्यों के बीच तुलना में यह बढ़ोतरी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल और त्रिपुरा में दिखाई पड़ती है जो 30% से भी ज्यादा है।

  गुजरात44.7% से बढ़कर 84% हो गया है 2020 में। प्रतिशत में यह बढ़ोतरी सरकारी व निजी दोनों तरह के विद्यालयों में नामांकित बच्चों के घरों में एक जैसी है। गुजरातमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है जो 39% से भी ज्यादा है।
- मार्च 2020 में स्कूल बंदी से पहले अथवा बाद में चाहे जब भी हासिल की हों, 80% से ज्यादा बच्चों के पास उनकी वर्तमान कक्षा की पाठ्यपुस्तकें मौजूद हैं। यह प्रतिशत सरकारी विद्यालयों के बच्चों (84.1%) में निजी विद्यालयों के बच्चों (72.2%) से ज्यादा है। राज्यों के लिहाज से यह प्रतिशत सिर्फ तीन राज्यों में 70% से नीचे दिखाई देता है: राजस्थान (60.4%), तेलंगाना (68.1%) और आंध्र प्रदेश (34.6%)।

  गुजरात में95% से ज्यादा बच्चों के पास उनकी वर्तमान कक्षा की पाठ्यपुस्तकें मौजूद हैं। यह प्रतिशत सरकारी विद्यालयों के बच्चों (95.2%) में निजी विद्यालयों के बच्चों (94%) है।

सीखने में घर का सहयोग

असर 2020 के आंकड़े बताते हैं कि माता-पिता का शैक्षित स्तर चाहे जो भी रहा हो, परिवारों से बच्चों की पढ़ाई में भरपूर सहयोग मिल रहा है।

- जबकि विद्यालय बंद हैं, करीब तीन चौथाई बच्चों को पढ़ाई में परिवार के सदस्यों से किसी न किसी किस्म का सहयोग मिल रहा है। गौरतलब है कि उन बच्चों को भी जिनके माता-पिता प्राइमरी से आगे नहीं पढ़ पाए, अपनी पढ़ाई में परिजनों से मदद मिली है। ऐसे परिवारों में बड़े भाई-बहन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

- छोटी कक्षाओं के बच्चे बड़ी कक्षाओं के बच्चों की बनिस्बत ज्यादा मदद पा रहे हैं। इसी तरह, ज्यादा पढ़े-लिखे माता-पिताओं के बच्चों को कम पढ़े-पढ़े लिखे माता-पिताओं के मुकाबले ज्यादा मदद मिल रही है। उदाहरण के लिए 54.8% बच्चे जिनके माता-पिता ने पांचवीं कक्षा या उससे कम शिक्षा पाई है, 89.4% उन बच्चों की तुलना में जिनके माता-पिता 10वीं या उससे ज्यादा शिक्षित हैं, किसी न किसी किस्म की पारिवारिक मदद पा रहे हैं।

  गुजरात में72.7% बच्चे जिनके माता-पिता ने पांचवीं कक्षा या उससे कम शिक्षा पाई है, 86.9% उन बच्चों की तुलना में जिनके माता-पिता दोनो ने 11वीं से ज्यादा शिक्षित हैं, किसी न किसी किस्म की पारिवारिक मदद पा रहे हैं।

- जैसे-जैसे बच्चे बड़ी कक्षाओं में पहुंच रहे हैं, माता-पिता से मिलने वाली मदद घट रही है। उदाहरण के लिए, कक्षा 1-2 के 33% बच्चों की माताएं उनकी मदद कर पा रही हैं जबकि कक्षा 9 और ऊपर के 15% बच्चों को ही अपनी माताओं से मदद मिल पा रही है। लेकिन बड़ी कक्षाओं के बच्चों को उनके बड़े भाई-बहनों से मिलने वाला सहयोग लगातार ज्यादा अहम होता जा रहा है।

शिक्षण सामग्री एवं गतिविधियों तक पहुंच

स्कूल बंदी के दौरान सरकार और अन्य संस्थाओं ने विविध किस्म की पाठ्यसामग्री बच्चों तक पहुंचाने के लिए कई तरीके अपनाए। इनमें पाठ्यपुस्तकें या वर्कशीट जैसी परंपरागत सामग्री का उपयोग, ऑनलाइन या रिकार्ड किए हुए पाठ, और फोन या हाथों-हाथ पहुंचाए गए वीडिओ व अन्य सामग्री शामिल हैं। असर 2020 में पूछा गया कि क्या सितंबर 2020 में सर्वे से ठीक पहले हफ़्ते में परिवारों को विद्यालय से इस तरह की कोई सामग्री पहुंची थी।

- कुल मिलाकर नामांकित बच्चों में से लगभग एक तिहाई को असर सर्वे से एक हफ्ता पहले अपने शिक्षकों से किसी न किसी किस्म की शिक्षण सामग्री या गतिविधि मिली थी। यह अनुपात छोटी कक्षाओं की तुलना में बड़ी कक्षाओं के बच्चों में ज्यादा था। इसी तरह सरकारी विद्यालयों की तुलना में निजी स्कूल के बच्चों में भी ज्यादा देखा गया।

- बच्चों को शिक्षण सामग्री अथवा गतिविधियों उपलब्ध कराने के मामले में विभिन्न राज्यों के बीच उल्लेखनीय अंतर पाया गया। जिन राज्यों में एक चौथाई से भी कम बच्चों को ही किसी भी किस्म की शिक्षण सामग्री मिल पाई, वे हैं- राजस्थान (21.5%), उत्तर प्रदेश (21%) और बिहार (7.7%)। गुजरात में 82%बच्चों को शिक्षण सामग्री अथवा गतिविधियों उपलब्ध हुई।

- विद्यालय चाहे किसी भी किस्म का हो, शिक्षण सामग्री को पहुंचाने के लिहाज से व्हाट्सएप सबसे लोकप्रिय माध्यम साबित हुआ है। यद्यपि इस मामले में निजी विद्यालयों के बच्चों का प्रतिशत (87.2%) सरकारी विद्यालयों के बच्चों (67.3%) से ज्यादा है। गुजरात में भी व्हाट्सएप के मामले में निजी विद्यालयों के बच्चों का प्रतिशत (86.2%) सरकारी विद्यालयों के बच्चों (61.6%) से ज्यादा है

- दूसरी ओर, शिक्षक के साथ निजी संपर्क के मामले में सरकारी विद्यालयों के बच्चे (31.8%) निजी विद्यालयों के बच्चों (11.5%) से कहीं आगे दिखाई देते हैं। इस संपर्क में शिक्षक द्वारा बच्चे के घर जाना या किसी परिजन का शिक्षक से विद्यालय जाकर मिलना शामिल है।

  गुजरात-दूसरी ओर, शिक्षक के साथ निजी संपर्क के मामले में सरकारी विद्यालयों के बच्चे (79.2%) निजी विद्यालयों के बच्चों (77%) से कहीं आगे दिखाई देते हैं। इस संपर्क में शिक्षक द्वारा बच्चे के घर जाना या किसी परिजन का शिक्षक से विद्यालय जाकर मिलना शामिल है।

- मोटे तौर पर जिन दो-तिहाई परिवारों ने बताया कि उन्हें उक्त अवधि में किसी भी किस्म की सामग्री नहीं मिली, उनमें से अधिकांश का कहना था कि विद्यालय ने उन्हें कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई।

शैक्षिक सामग्री और गतिविधियों में बच्चों की हिस्सेदारी

शैक्षिक सामग्री व गतिविधियों में निरंतर हिस्सेदारी, सीखने की प्रक्रिया में होने वाले ह्रास को रोकने का अहम उपाय है। असर 2020 में पूछा गया कि क्या बच्चों ने पिछले हफ़्ते किसी किस्म की शैक्षिक गतिविधि में हिस्सा लिया, भले ही विद्यालय ने उस दौरान कोई शैक्षिक सामग्री भेजी अथवा नहीं।

- यद्यपि एक तिहाई बच्चों को ही सर्वे के पहले हफ़्ते में उनके शिक्षकों से किसी किस्म की शिक्षण सामग्री मिली थी। ज़्यादातर (70.2%) बच्चों ने किसी न किसी किस्म की शैक्षिक गतिविधि में हिस्सा लिया था। स्कूल के अलावा अथवा उसकी जगह इन गतिविधियों के स्रोत विविध थे, जैसे- ट्यूशन टीचर और परिवार में से ही कोई सदस्य।

  गुजरातमें ज़्यादातर (92.0%) बच्चों ने किसी न किसी किस्म की शैक्षिक गतिविधि में हिस्सा लिया था।

- सबसे ज्यादा उपयोग में लाई गई शिक्षण सामग्री थी पाठ्यपुस्तक (59.7%) और वर्कशीट (35.3%)। सरकारी और निजी विद्यालयों के बच्चों का अनुपात इस उपयोग के मामले में एक जैसा था।

  गुजरात-सबसे ज्यादा उपयोग में लाई गई शिक्षण सामग्री थी पाठ्यपुस्तक (81.6%) और वर्कशीट (36.8%)। सरकारी और निजी विद्यालयों के बच्चों का अनुपात इस उपयोग के मामले में एक जैसा था।

- विद्यालय की प्रकृति का एक मामले में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, वह है ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच। इस लिहाज से निजी विद्यालयों के बच्चे सरकारी विद्यालयों से साफ तौर पर आगे हैं। उदाहरण के लिए, निजी विद्यालयों के 28.7% बच्चों ने वीडिओ या अन्य तरह की पहले से रिकार्ड की गई पाठ्यसामग्री ऑनलाइन देखी थी, जबकि सरकारी विद्यालयों में यह प्रतिशत मात्र 18.3% देखा गया।

  गुजरातमें निजी विद्यालयों के 67.4% बच्चों ने वीडिओ या अन्य तरह की पहले से रिकार्ड की गई पाठ्यसामग्री ऑनलाइन देखी थी, जबकि सरकारी विद्यालयों में यह प्रतिशत मात्र 50.6% देखा गया।

- सभी बच्चों में करीब एक तिहाई का, सर्वे के ठीक पहले वाले हफ़्ते में शिक्षक के साथ किसी न किसी किस्म का निजी संपर्क हुआ था।

नीतिगत अनुमान

बच्चों की शिक्षा में कम से कम व्यवधान पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार व अन्य संस्थाओं द्वारा उठाए गए कदमों की थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य मिलती है लेकिन इन उपायों की पहुंच बच्चों तक कितनी हो पा रही है, इस बारे में व्यवस्थित व सकल सूचनाएं उपलब्ध नहीं है। असर 2020 इन मुद्दों पर राज्य व राष्ट्र स्तर पर आंकड़े उपलब्ध कराने वाला पहला सर्वेक्षण है। इन निष्कर्षों से बनने वाली समझ देश के लिए निम्न महत्वपूर्ण नीतिगत संभावनाओं की ओर संकेत करती है:

अस्थिर परिस्थिति: जब विद्यालय दोबारा खुलते हैं तो इस बात पर नज़र बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन वापस वापस लौट रहा है। साथ ही यह जानना भी जरूरी होगा कि पिछले वर्षों की तुलना में सीखने में होने वाली गिरावट कितनी है।

पारिवारिक सहयोग को आधार बनाना व मजबूत करना:अभिभावकों के बढ़ते शैक्षिक स्तर को नई शिक्षा नीति के सिफारिशों के अनुरूप बच्चों के अधिगम सुधार की योजनाओं से जोड़ा जा सकता है। पालक अपने बच्चों को कैसे मदद कर सकते हैं, यह जानने के लिए "सही स्तर पर माता-पिता तक पहुंचना" जरूरी है। इस मामले में बड़े भाई-बहन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

“हाइब्रिड” लर्निंग: बच्चे घर पर कई तरह की गतिविधियां करते हैं। मिश्रित शिक्षा (हाइब्रिड लर्निंग) के प्रभावी तरीकों को ढूंढने की ज़रूरत है। परंपरागत “टीचिंग-लर्निंग” के साथ नई “रीचिंग-लर्निंग” पद्धतियों को जोड़ने के तौर-तरीके खोजने की आवश्यकता है।

डिजिटल प्रणालियों व पाठ्यसामग्री का प्रभाव: डिजिटल पाठ्यसामग्री को उपलब्ध कराने की कई प्रणालियों को परखा गया है। भविष्य में डिजिटल सामग्री व उसकी पहुंच को बेहतर बनाने के लिए जरूरत इस बात की है कि क्या काम करता है, कितने बेहतर ढंग से करता है, किन तक पहुंच पाता है और कौन छूट जाता है, जैसे सवालों का गहराई से आकलन हो।

“डिजिटल विभाजन” की भरपाई: जैसा कि अपेक्षित है जो परिवार कम शिक्षित हैं और साथ ही स्मार्टफोन जैसे संसाधनों से भी वंचित हैं, शिक्षा के अवसरों से और दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे परिवारों के बीच भी प्रयास किए जाने के प्रमाण है: परिवार के सदस्य जो मदद की कोशिश करते हैं और विद्यालय जो उन तक पहुंचने के प्रयास करते हैं। विद्यालयों को खुलने के बाद इन बच्चों को औरों के बनिस्बत ज़्यादा मदद की दरकार होगी। ऐसे पालकों के साथ नज़दीकी संपर्क बनाने की ज़रूरत पड़ेगी।

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें

Chirag Vyas
Email: chirag.vyas@pratham.org

Mobile: 9426987164